

आउटकम बजट 2024-25

विभाग का नाम-परिवहन विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0-11
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31-3-2024 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2024-25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024-25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	परिवहन आयुक्त/संभागीय कार्यालयों के अनावासीय भवन भूमि क्रय	परिवहन कार्यालयों को राजकीय भवनों में स्थापित/संचालित करना तथा कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनको होने वाली आवासीय समस्या के समाधान हेतु आवासीय भवनों का निर्माण करना।	-	700.00	राज्य के 06 आयुक्त/संभागीय कार्यालयों के अनावासीय भवन भूमि क्रय का निर्माण कार्य गतिमान/ भौतिक स्थिति निम्नवत:- 1. कर्णप्रयाग - 60 % 2. काशीपुर - 45 % 3. उत्तरकाशी - 10 % रूडकी, रामनगर एवं पिथौरागढ़ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा प्रक्रिया संपादित (शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि आवंटित)।	1. कर्णप्रयाग - 80 % 2. काशीपुर - 65 % 3. उत्तरकाशी - 30 % 4. रूडकी - 30 % 5. रामनगर - 30 % 6. पिथौरागढ़ - 30 %	07 अनावासीय भवनों (विकासनगर, रूद्रप्रयाग, टिहरी, रानीखेत, बागेश्वर, हल्द्वानी एवं चम्पावत) का निर्माण किया जाना।	कार्यालयों को राजकीय भवन में स्थापित किए जाने से कार्मिकों द्वारा राजकीय कार्यों का संपादन सुचारु रूप से किया जाएगा, जिससे स्थानीय जनता को अपने परिवहन संबंधी कार्यों को कराने में सुविधा प्राप्त होगी।	31.03.2025
2	किच्छा खटीमा बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि अर्जन का प्रतिकर	परिवहन सेवा का सुदृढीकरण।	-	0.01	-	-	रेल लाईन निर्माण	किच्छा खटीमा रेल लाईन निर्माण से यात्रियों को आवागमन हेतु सुविधा मिलेगी।	-
3	मुजफ्फरनगर-रूडकी रेल लाईन निर्माण	परिवहन सेवा का सुदृढीकरण।	-	0.01	-	-	रेल लाईन निर्माण	मुजफ्फरनगर - रूडकी रेल लाईन निर्माण से यात्रियों को आवागमन हेतु सुविधा मिलेगी।	-
4	हल्द्वानी में आई०एस०बी० टी० की स्थापना	हल्द्वानी में सभी प्रकार की परिवहन सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाना।	-	1000.00	-	-	ISBT का निर्माण।	आईएसबीटी के निर्माण से आम जनता/ यात्रियों को सुलभ आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।	31.03.2025
5	व्हीकल टेस्टिंग	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में	-	2000.00	पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में	1. पिथौरागढ़-20%	वाहनों की स्वस्थता	पूर्व में वाहनों की	31.03.2025

	सेन्टर का निर्माण	वाहनों के फिटनेस परीक्षण हेतु।			ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ए०टी०एस०) के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि अवमुक्त, कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य गतिमान। अल्मोड़ा हेतु शासन द्वारा डी०पी०आर० स्वीकृत। आवंटित धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने की कार्यवाही गतिमान।	2. उत्तरकाशी- 20% 2. अल्मोड़ा- 10%	जाँच हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 04 स्थानों यथा-पिथौरागढ़, उत्तरकाशी अल्मोड़ा एवं पौड़ी में ए०टी०एस० का निर्माण।	स्वस्थता जाँच मैनुअल आधार पर की जा रही थी, वही अब स्वचालित रूप से किए जाने के दृष्टिगत वाहन स्वामियों को स्वस्थता प्रमाण पत्र मानवीय हस्तक्षेप के बिना ऑनलाइन प्राप्त होंगे। अस्वस्थ वाहनों से होने वाली दुर्घटना तथा प्रदूषण में कमी आएगी।	
6	हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय/ भवन निर्माण	कुमायूँ क्षेत्र में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना।	-	1000.00	-	-	देहरादून के सदृश्य राज्य के कुमाऊँ मण्डल के हल्द्वानी में भी चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण।	चालक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित दक्ष वाहन चालकों द्वारा वाहन संचालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी।	31.03.2025
7	चालकों के परीक्षण हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक्स का निर्माण	दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चालकों का परीक्षण।	-	1000.00	हरिद्वार, ऋषिकेश एवं कोटद्वार में सिविल कार्य पूर्ण। 1. काशीपुर - 20% 2. अल्मोड़ा - 5% 3. उत्तरकाशी - 5% पिथौरागढ़, रुड़की, रामनगर एवं हल्द्वानी में ADTT निर्माण हेतु शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त।	03 स्थानों (हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार) में निर्मित ट्रेक्स के ऑटोमेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। 1. काशीपुर 40 % 2. अल्मोड़ा-25 % 3. उत्तरकाशी- 25% 4. पिथौरागढ़- 20% 5. रुड़की- 20 % 6. रामनगर- 20 % 7. हल्द्वानी- 20%	09 कार्यालयों में (रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, विकासनगर उधमसिंह नगर, बागेश्वर, टनकपुर, कर्णप्रयाग एवं रानीखेत) ट्रेक्स का निर्माण ऑटोमेशन सहित किया जाना है।	ट्रेक्स पर परीक्षण से कुशल चालकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।	31.03.2025
8	उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति को अनुदान	सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ीकरण।	2314.00	-	समस्त जनपदों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन, फर्स्ट रिस्पोंडर ट्रेनिंग, स्पीडरडार गन (13) प्रवर्तन दल को दिए गए।	-	ए०एन०पी०आर० परियोजना (तृतीय चरण), फर्स्ट रिस्पोंडर प्रशिक्षण प्रदान एवं समस्त जनपदों में सड़क सुरक्षा	ए०एन०पी०आर० कैमरों के स्थापित होने से ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, जिससे सड़क	31.03.2025

							जागरूकता अभियान संचालित करना। प्रवर्तन वाहनों के ईंधन अनुरक्षण एवं उन पर तैनात चालकों के वेतन आहरण हेतु।	दुर्घटनाओं में कमी आएगी। प्रभावी प्रवर्तन से राजस्व में वृद्धि होगी।	
9	वाहन चालकों को प्रशिक्षण	वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।	60.00	—	—	—	चालक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से SC/ST/OBC / EWS एवं महिलाओं को परिवहन वाहनों के संचालन का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें प्रति प्रशिक्षु (कुल 400 प्रशिक्षु) रु 25,000 का व्यय संभावित है, रु 100 प्रतिदिन मानदेय देय।	चालक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित चालको को कुशलता पूर्वक वाहन संचालन औपचारिकता पूर्ण उपरान्त ही कुशल चालकों को ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में भी कमी होगी।	31.03.2025
10	चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहन चालकों हेतु विश्राम, चिकित्सा एवं अन्य सुविधा	चारधाम यात्रा हेतु वाहन चालकों के कल्याणार्थ विश्राम/प्रवास, चिकित्सा परीक्षण, रिफ्रेशर कोर्स एवं दुर्घटना बीमा आदि।	1000.00	—	—	—	चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले व्यवसायिक वाहन चालकों (01 लाख) को बीमा की सुविधा (अनुमानित लागत रु 5.00 करोड़) तथा बद्दीनाथ/केदारनाथ में आने वाले व्यवसायिक वाहन चालको (200 चालकों) के लिए विश्रामालय, भोजनालय इत्यादि की स्थापना (अनुमानित लागत रु 5.00 करोड़)	चारधाम यात्रा पर आने वाले वाहन चालको को विश्राम/प्रवास/ भोजनालय/ चिकित्सा परीक्षण/दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान होने से चारधाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढोत्तरी होने से राज्य के राज्यकोष में वृद्धि होगी।	31.03.2025
11	इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन	इलैक्ट्रिक गतिशीलता को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार	0.01	—	—	—	इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान करना। टेक्स छूट आदि दिया जाना।	इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रित होने में मदद होगी। प्रदूषण	31.03.2025

		लाना तथा राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में सक्षम बनाना।						में कमी के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।	
12	ग्रीन सैस से प्राप्त धनराशि का शहरी परिवहन अवसंरचना निधि में अंतरण	शहरी यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा का सुदृढीकरण।	1000.00	—	राज्य में 05 स्थानों (देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी) में ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाने हैं।	कार्यदायी संस्थाओं से डी०पी०आर० के गठन की कार्यवाही गतिमान है।	शहरी यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा हेतु प्रभावी कार्यवाही।	शहरी यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा हेतु प्रभावी कार्यवाही से दुर्घटनाओं में कमी।	31.03.2025
नाबार्ड पोषित									
13	ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन, चालक प्रशिक्षण संस्थान	वाहनों के फिटनेस परीक्षण तथा चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम करना।	—	0.01	—	—	—	—	—
नई मांग									
14	अरबन मोबिलिटी कार्यक्रम	नगरीय यातायात को सुदृढ किया जाना।	1000.00	—	—	—	उत्तराखण्ड राज्य में नगरीय यातायात को सुदृढ करने के उद्देश्य से प्रत्येक नगर में अरबन मोबिलिटी प्लान लागू किया जाना।	देहरादून नगर में यातायात को निर्बाध एवं सुचारु रूप से संचालित किया जाना सम्भव हो सकेगा। इस योजना के अंतर्गत नगर में संचालित 250 बसों/विक्रम वाहनों को सी०एन०जी०/ इलैक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाना है।	31.03.2025
15	प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण	बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना।	—	1000.00	—	—	राज्य में 04 स्थानों पर (देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा) में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क विकसित किया जाना है।	चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के निर्माण से बच्चों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। जिससे दुर्घटनाओं	31.03.2025

								में कमी होगी।	
16	ई0वी0 चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण	ई0वी0 चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना।	-	1000.00	-	-	इलैक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ई0वी0 चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना।	ई0वी0 चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत EV Charging Station की स्थापना की जाएगी, जिससे इलैक्ट्रिक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को अपने वाहन की बैटरी चार्ज करने की सुविधा प्राप्त होगी अर्थात Last Mile Connecting को बढ़ावा मिलेगा। इससे इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण के स्तर में कमी आयेगी।	31.03.2025

(डॉ० अनीता चमोला)
सहायक परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।